भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- 429

उत्तर देने की तारीख-23/03/2026

भागलपुर में केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय की स्थापना

*429. **श्री अजय कुमार मंडल:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बिहार के भागलपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय या अन्य केंद्रीय शिक्षण संस्थान स्थापित करने का विचार है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों को भरने के लिए कोई विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण स्कूलों में डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लासरूम सुविधाएं बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए बजटीय प्रावधान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत भागलपुर के छात्रों को वितरित की गई कुल निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

माननीय संसद सदस्य श्री अजय कुमार मंडल द्वारा "भागलपुर में केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय की स्थापना" के संबंध में दिनांक 23.03.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 429 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) नए केंद्रीय विद्यालय (केवि) खोलना एक सतत् प्रक्रिया है। केवि पूरे देश में शिक्षा का एक समान कार्यक्रम प्रदान करने हेतु मुख्य रूप से केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों सहित रक्षा और अर्ध-सैन्य कर्मियों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान (आईएचएल) के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं। नए केवि खोलने के प्रस्तावों को भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों द्वारा प्रायोजित किया जा सकता है जिसमें केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) के मानदंडों के अनुसार एक नया केवि स्थापित करने के लिए निःशुल्क अपेक्षित भूमि और उपयुक्त किराया-मुक्त अस्थायी आवास को उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता शामिल होती है। वर्तमान में, बिहार में 51 केवि कार्यात्मक हैं, जिनमें एनटीपीसी कहलगांव, भागलपुर जिले में एक केवि शामिल है।

भारत सरकार ने हाल ही में अक्टूबर, 2025 में देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें बिहार के भागलपुर जिले के भागलपुर टाउन में एक केवि शामिल है।

नवोदय विद्यालय योजना में देश के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय (नवि) खोलने की परिकल्पना की गई है। नए नवोदय विद्यालय खोलना एक सतत् प्रक्रिया है जो स्थायी भवन के निर्माण हेतु निशुल्क अपेक्षित उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने और स्थायी भवन का निर्माण होने तक विद्यालय संचालित करने के लिए किराया-मुक्त अपेक्षित अस्थायी भवन निःशुल्क उपलब्ध कराने की संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की इच्छा पर निर्भर करती है। मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार नए नवि की संस्वीकृति और उन्हें खोला जाना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर निर्भर करता है। वर्तमान में बिहार के सभी 38 जिलों में 39 नवि कार्यात्मक हैं, जिनमें भागलपुर ज़िले में स्थित 1 नवि शामिल है।

भारतीय आईटी उद्योग की बढ़ती कौशल चुनौतियों और घरेलू आईटी बाजार के विकास को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा मंत्रालय ने आईटी में विश्व स्तरीय मानव संसाधन प्रदान करने, देश में आईटी उद्योग हेतु उपलब्ध मानव पूंजी को विकसित करने/सुदृढ़ करने और विभिन्न क्षेत्रों में आईटी के बहुआयामी पहलुओं का उपयोग करने की संकल्पना के साथ भारत में पांच केंद्रीय

वित्त पोषित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) और गैर लाभकारी सार्वजनिक निजी भागीदारी पर बीस आईआईआईटी की स्थापना की है, इन आईआईआईटी में से पीपीपी मोड के अंतर्गत एक आईआईआईटी, नामतः आईआईआईटी (पीपीपी) भागलपुर, वर्ष 2017 में बिहार के भागलपुर जिले में स्थापित किया गया था।

इसके अतिरिक्त, बिहार के भागलपुर में स्थित विक्रमशिला के ऐतिहासिक स्थल के समीप एक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु, बिहार राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण करने का अनुरोध किया गया है।

केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाएं (सीईआई) खोलना एक सतत प्रक्रिया है जो मौजूदा प्रक्रिया/नीति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर निर्भर करती है। 'शिक्षा' एक समवर्ती विषय होने के कारण, राज्य सरकारें भी अपने-अपने राज्यों में स्कूल/उच्चतर शिक्षा तक अपेक्षाकृत अधिक पहुंच प्रदान करने के लिए विभिन्न पहलें कर रही हैं।

(ख) सितंबर 2022 से, सभी केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (सीएचईआई) ने रिक्त पदों को भरने के लिए मिशन मोड में भर्ती अभियान चलाया है। दिनांक 24.01.2026 (अर्थात पिछले रोज़गार मेले की तारीख) तक, सभी सीएचईआई द्वारा कुल 30720 पद भरे गए हैं। ब्यौरा संलग्न है।

पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, नई संस्थाओं, योजनाओं या परियोजनाओं के खुलने और मौजूदा संस्थाओं में छात्रों की बढ़ी हुई संख्या तथा क्षमता विस्तार से जनित अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है और संबंधित भर्ती नियमावली के प्रावधानों के अनुसार रिक्तियों को भरने के प्रयास किए जाते हैं।

(ग) समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत आईसीटी और डिजिटल पहल घटक के तहत, स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशाला और स्मार्ट कक्षाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। भागलपुर निर्वाचन क्षेत्र में आईसीटी प्रयोगशाला और स्मार्ट कक्षा की स्थापना हेतु वर्ष 2025-26 के लिए बजटीय प्रावधान इस प्रकार हैं:

विवरण	बजटीय प्रावधान (रू. लाख में)
आइसीटी प्रयोगशाला (नई)	1257.10
स्मार्ट कक्षा (नई)	576.00
आइसीटी प्रयोगशाला (पुरानी)	160.80
स्मार्ट कक्षा (पुरानी)	99.60
कुल	**2093.50**

(घ) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रशासित केंद्रीय क्षेत्र योजना 'राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने से रोकने और माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। मेधावी छात्र चयन परीक्षा और योजना के पात्रता मानदंडों के माध्यम से चुने जाते हैं। प्रत्येक वर्ष कक्षा IX के चयनित मेधावी छात्रों को प्रति वर्ष प्रति छात्र 12000/- रुपये की दर से एक लाख नई छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं और राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त या स्थानीय निकाय स्कूलों में अध्ययन हेतु कक्षा X, XI और XII में उनका जारीकरण/नवीनीकरण किया जाता है। मेधावी छात्रों के चयन हेतु प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को एक निश्चित कोटा आवंटित किया जाता है। जिला/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए कोई विशिष्ट कोटा निर्धारित नहीं है। इस योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, भागलपुर सहित बिहार राज्य के छात्रों को 17.83 करोड़ रुपये (लगभग) की 14,857 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं।

उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन [पीएम-यूएसपी] योजना, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसके तहत गरीब और मेधावी छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जो छात्र बारहवीं कक्षा में सफल अभ्यर्थियों के शीर्ष 20 प्रतिशत में हैं और जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष 4.5 लाख रुपये तक है, वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं। एक वर्ष में, 82,000 नए छात्रवृत्ति स्लॉट उपलब्ध होते हैं। इन्हें राज्य की 18-25 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या के आधार पर राज्य शिक्षा बोर्डों के बीच विभाजित किया गया है। छात्राओं के लिए 50% छात्रवृत्ति स्लॉट निर्धारित हैं। जिला/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए कोई विशिष्ट कोटा निर्धारित नहीं है। इस योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, भागलपुर सहित बिहार राज्य के छात्रों को 66.98 करोड़ रुपये (लगभग) की 55,255 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं।

*****

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य श्री अजय कुमार मंडल द्वारा "भागलपुर में केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय की स्थापना" के संबंध में दिनांक 23.03.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 429 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं द्वारा मिशन मोड में भर्ती के तहत सितंबर 2022 से दिनांक 24.01.2026 तक की गई नियुक्तियाँ

संस्थाएं	की गईं नियुक्तियाँ		
	संकाय	गैर-संकाय	कुल
सीयू	8465	4403	12868
आईआईटी	3285	4532	7817
आईआईआईटी	470	188	658
आईआईएम	537	379	916
एनआईटी	4644	2421	7065
आईआईएसईआर/आईआईएससी	305	387	692
बीओएटी/एनआईटीटीआर/स्टैंडअलोन संस्थाएं	133	354	487
एसपीए	39	43	82
भाषा संस्थाएं	0	44	44
अन्य (एनआईईपीए/अनुसंधान परिषदें/एआईसीटीई/एडसिल/यूजीसी/मंत्रालय मुख्यालय/एनबीटी/एनसीएमईआई आदि)।	0	91	91
कुल	**17878**	**12842**	**30720**

*****